Volume-1 | Issue-2 | Apr. 2011 - Jun 2011

e-mail: uaslsa_02@yahoo.co.in

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

High Court Campus, Nainital - 263001 Tel. : 05942-236762, Fax : 05942-236552 www.slsk.uk.gov.in

NEWS LETTER

A quarterly newsletter published by Uttarakhand SLSA.

Legal Awareness Camp for the Transgender Community

अल्मोड़ा/बागेश्वर जागरण बागेश्वर, 17 फरवरी 2011 दैनिक जागरण | 7

उत्पीड़न पर तुरंत शिकायत करें किन्नर

विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करती सीजेएम मोनिका मित्तल। जागरण

शिविर

- शिविर लगाकर दी किन्नरों को कानूनी जानकारी

जागरण कार्यालय, बागेश्वर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय में साक्षरता शिविर लगाकर किन्नरों को विधिक जानकारी दी। इस दौरान सीजेएम मोनिका मित्तल ने किन्नरों से अपील की कि वह उत्पीड़न होने की स्थिति में तुरंत कानून की मदद लें।

किन्नरों को संबोधित करते हुए सीजेएम ने कहा कि किन्नर समुदाय स्वयं को उपेक्षित व समाज से पृथक न समझें। बल्कि उन्हें भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि आम आदमी को हैं। कहा कि किन्नरों को अपमानित व प्रताड़ित करने वालों पर कानून कार्रवाई करेगा। इस दौरान उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने, उत्पीड़न, सूचना का अधिकार, छेड़छाड़ आदि कानूनों की विस्तार से जानकारी दी गयी।

शिविर में किन्नरों ने भी अपनी समस्याओं से सीजेएम मोनिका मित्तल को अवगत कराया। विधिक शिविर में बलवंत रावल, पूजा, किरन, सीमा, राजू, मिन्टू, विनय सुयाल, प्रमोद नौटियाल, दुष्यंत पाराशर, प्रकाश उपाध्याय व दिवाकर वर्मा आदि मौजूद थे।

DLSA Bageshwar apprising the Transgender Community about their legal rights.

Uttarakhand State Legal Services Authority has taken the initiative towards the welfare of the Transgender Community who face regular harassment and abuse under allegations of creating a nuisance and soliciting sex work.

Considering the grave socio-legal problems being faced by the members of the Transgender Community and under the valuable guidance given by Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, a total no. of 15 legal awareness camps and seminars were organized for the transgender community from January, 2011 to February, 2011 by the District Legal Services Authorities throughout the State, wherein a total no. of 58 Transgender were enlightened about their constitutional and legal rights.

नैनीताल, 25 फरवरी 2011 दैनिक जागरण | 5

पिथौरागढ में विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित अधिकारी व किन्नर। जागरण

पहल : किन्नरों को बताईं कानून की बारीकियां

आयोजन

- पिथौरागढ में पहली बार किन्नरों के लिए आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

जागरण कार्यालय, पिथौरागढ: जिला मुख्यालय पर गुरुवार को पहली बार किन्नरों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किन्नरों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरके मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में किन्नरों को महत्वपूर्ण विधिक जानकारियां दी गईं। साथ ही किन्नरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। शिविर में तहसीलदार नरेश दुर्गापाल, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन चंद भट्ट, अधिवक्ता दिनेश चंद्र पंत, सुभाष सिंह, किन्नर रामविलास, काछी, मंजू, पूजा सिंह आदि मौजूद थे। जिले में पहली बार किन्नरों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था।

शारीरिक विकलांगता प्रगति में बाधक नहीं

अल्मोड़ा के नगरपालिका सभागार में विशेष किन्नर दिवस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विध्यांचल सिंह व अन्य। जागरण

प्रेरणा

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मनाया विशेष किन्नर दिवस
- कहा, समाज में मानवीय गरिमा के है पूरे हकदार

जागरण कार्यालय, अल्मोड़ा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष किन्नर दिवस का आयोजन किया गया। नगरपालिका सभागार में आयोजित गोष्ठी में किन्नर समुदाय के लोगों से चर्चा परिचर्चा के दौरान उनकी समस्याओं के बारे में व विधिक साक्षरता पर जानकारी दी गई।

गोष्ठी में मौजूद किन्नर समुदाय की गुरु गुड्डी का कहना था कि वह पढ़ना, लिखना और एक आम आदमी की तरह जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन समाज का नजरिया उनके प्रति उपेक्षा का रहा है। जो हमेशा उनके लिए गहन पीड़ा का कारण बनता है। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विध्यांचल सिंह ने, कहा कि शारीरिक विकलांगता मनुष्य के जीवन की प्रगति में बाधक कतई नहीं है। उन्होंने किन्नर समुदाय के लोगों का आह्वान किया कि वह लोग वह सारे काम करने में सक्षम हैं, जिसे समाज के बाकी लोग करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय में उनका वैसा ही अधिकार है, जैसा समाज के हर व्यक्ति का।

सीनियर डिवीजन जज अरविंद कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21ए के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किन्नर भी समाज में मानवीय गरिमा के हकदार हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेखर,लखचौरा ने भी किन्नर समाज को समाज का महत्वपूर्ण अंग बताया। इस मौके पर रमेश नेगी, दीपक वाल्मीकि, पंकज लटवाल, रमेश सिंह दानू, भूपेंद्र मियान, अकबर खान ने भी समाज के नजरिये में बदलाव की बात कही। गोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विध्यांचल सिंह व संचालन एडवोकेट रमाशंकर नैनवाल ने किया। गोष्ठी में रमेश लोहनी, भगवती प्रसाद पंत, घनश्याम जोशी, अनुज साह, हरीश लोहनी, विजय जोशी, सुनील कुमार, पंकज त्रिपाठी, जगदीश चंद्र सहित किन्नर समुदाय की पिंकी, सलीम, शमशाद सहित अनेक लोग मौजूद थे।

Mega Lok Adalat

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA delivering presidential address on the eve of Mega Lok Adalat on 25th March, 2011 at Dehradun.

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA, Hon'ble Mr. Justice Barin Ghosh, Chief Justice, High Court of Uttarakhand & Patron-In-Chief, UKSLSA with Hon'ble Mr. Justice Tarun Agarwala, Sr. Judge, High Court of Uttarakhand & Executive Chairman, UKSLSA taking round of the Courts organizing Mega Lok Adalat on 25th March, 2011 at Dehradun.

सहारा

मिनटों में निपटे वर्षों से लटके हजारों केस

मिनटों में...

उन्होंने कहा कि पक्षकारों का उद्देश्य मुकदमा लड़ना नहीं होता। वे समाधान के दूसरे विकल्प पसंद करते हैं। अल्तमस कबीर ने सांकेतिक रूप से दो पक्षकारों को समझौते के बाद मुकदमे खत्म होने के कागजात सौंपे। उन्होंने कहा कि अदालत में मुकदमों का बोझ कम करने के लिए समाज के विभिन्न तबकों को आगे आकर काम करना होगा। झारखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां डाक्टर, वकील तथा अन्य लोग विवादों को समाप्त कराने में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्घाटन करने के साथ ही प्राधिकरण के न्यूज लेटर का विमोचन किया। इस असवर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण अग्रवाल के साथ देहरादून के न्यायिक अधिकारी मौजूद थे।

अदालतों का किया निरीक्षण

देहरादून। न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने विभिन्न अदालतों का निरीक्षण किया। वह मुकदमों की सुनवाई के दौरान अदालतों में गए। उन्होंने अदालती कार्यवाही देखी। इसके बाद उन्होंने मुकदमों के बारे में न्यायाधीशों से बात की।

कोर्ट में जज से बड़ा कोई नहीं

कोर्ट में जज से बड़ा कोई नहीं है। सभी पदों पर कानून से अधिकार प्रदान किए गए हैं। श्री कबीर जिन अदालतों में निरीक्षण के लिए गए वहां जजों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सम्मान में खड़े होने के प्रयास किया तो उन्होंने रोक दिया। कई जजों को उन्होंने इशारे से बताया कि वह कुर्सी पर बैठे रहें। कई अदालतों में वह तटस्थ रूप से खड़े रहे।

Pictorial View of main programme organized on the eve of Mega Lok Adalat on 25th March, 2011 at Dehradun.

With the motivation of Hon'ble Mr. Justice Barin Ghosh, Chief Justice / Patron-In-Chief, Uttarakhand State Legal Services Authority and under the valuable guidance of Hon'ble Mr. Justice Tarun Agarwala, Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority for providing the efficacious, inexpensive and expeditious justice to all, and to implement the motto of the establishment "Access to Justice for All", a MEGA LOK ADALAT was organized on 25th March, 2011, under the aegis of all the District Legal Services Authorities in all the Districts and Outlying Courts of the State. Hon'ble

देहरादून शनिवार, 26 मार्च 2011 देहरादून

वरिष्ठ न्यायाधीश अल्तमस कबीर को सम्मानित करते हाई कोर्ट के न्यायाधीश • हिन्दुस्तान

स्वच्छ, संवेदनशील, समर्पित व सहनशील बनें अधिकारी

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित मेगा लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अल्तमस कबीर की देख रेख में सपन्न हुई। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी वेबसाइट का शुभारम्भ किया। विधिक प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित न्यूज लेटर का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से अब तक पूरे देश में 18 लाख से अधिक वादों का निस्तारण किया गया है। इस अवसर पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तरूण अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। जिला जज राजकृष्ण, एडीजे प्रदीप पंत, श्रीकांत पांडे, सचिव मी सुल्तान, सी जेएम सीबीआई अनुराधा गर्ग, बार एसो. अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल, सचिव अनिल गांधी मौजूद रहे।

the pioneer

DEHRADUN I SATURDAY I MARCH 26, 2011

Lok Adalat settles 10,293 cases

PNS ■ DEHRADUN

A Mega Lok Adalat was organised in each district of Uttarakhand on Friday. However, the main function was held at Dehradun court premises where an inaugural ceremony was planned by Uttarakhand State Legal Services Authority.

The ceremony was marked by presence of several distinguished judges including Supreme Court Justice Altamas Kabir, Chief Justice of Uttarakhand High Court Justice Barin Ghosh and Justice Tarun Agarwal, chairman Uttarakhand State Legal Services Authority.

Although inaugural ceremony begins at noon at the Dehradun court premises, but the proceeding of Lok Adalat started on Friday morning. Litigants were present since morning. Notably students and faculty members of different law colleges also witnessed this mega event.

Chairman of Uttarakhand State Legal Services Authority Justice Tarun Agarawal has announced that more than 3,000 cases were disposed off in 12 districts of Uttarakhand while in Dehradun alone more than 3,500 cases were disposed off within an one hour of proceedings. However, a total of 10,293 cases were settled in Dehradun. Accident compensation for Rs 1,38,30,000 was granted in different cases, while fine worth Rs 6,33,030 has been awarded by 16 different courts in Dehradun in other cases.

Interestingly, first two couples, whose matrimonial disputes were sorted out through mediation, were called on stage to take blessing of judges. Matrimonial dispute of Saxena family was pending under CrPC under Section 125, while matrimonial dispute of Kapoor family which was under Hindu Marriage Act Section 13 were sorted out amicably. Both families have expressed their happiness after the settlement of dispute.

Earlier, judges visited courts of Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate and District Judge Dehradun, where they interacted with judges and asked about the status of the pending cases before courts. During his visit of family court, Dehradun Justice Kabir, asked the judge BS Duggal to sort out the cases of matrimonial disputes through the mediation.

However, official ceremony was started by lighting of ceremonial lamp by the judges of the Supreme Court and High Court. During his address, Justice Kabir, expressed his concern over lack of legal awareness in society, especially in hilly area of Uttarakhand. He said that it is the resolve of Legal Services Authority to reach out to those areas which are still looking for the service.

Admiring the Alternative Dispute Resolution System, Justice Kabir emphasised on arbitration, mediation and reconciliation for disposing off the civil cases. He also gave the new abbreviation of the Supreme court cases (SCC) i.e. S-Sensitive, C- Compassionate and C- Commitment.

दैनिक जागरण देहरादून, 26 मार्च 2011

लोक अदालत में 21 हजार मुकदमे निस्तारित

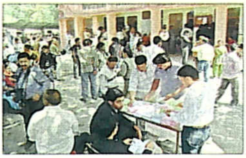

देहरादून में लगी मेगा लोक अदालत में पहुंचे वादकारी।

Pictorial View of main programme organized on the eve of Mega Lok Adalat on 25th March, 2011 at Dehradun.

Mr. Justice Altamas Kabir, Judge Supreme Court of India & Executive Chairman, National Legal Services Authority graced the said event at Dehradun in the presence of Hon'ble Mr. Justice Barin Ghosh, Chief Justice/Patron-In-Chief, Uttarakhand SLSA and Hon'ble Mr. Justice Tarun Agarwala, Executive Chairman, Uttarakhand SLSA. The Advocate General, Govt. of Uttarakhand, Member Secretary, NALSA, Registrar General, High Court of Uttarakhand, District Judge, Dehradun, Member Secretary, Uttarakhand SLSA, Senior Members and other Advocates from the Dehradun Bar, legal luminaries, law students and litigants in large number participated in the said event.

Pictorial View of main programme organized on the eve of Mega Lok Adalat on 25th March, 2011 at Dehradun.

The matters relating to MACT cases, Matrimonial cases, Revenue cases, Excise cases, cases relating to N.I. Act etc. were taken up in the said Mega Lok Adalat. In this Mega Lok Adalat, a total number of 19,319 cases of various natures were amicably and successfully decided. A sum of Rs. 3,66,43,045/- was awarded as compensation to the victims of Motor Accident and a fine in the tune of Rs 42,43,917/- was realized in the petty offences, wherein a total number of 20,588 person were benefited in this Mega Lok Adalat.

Website of Uttarakhand State Legal Services Authority

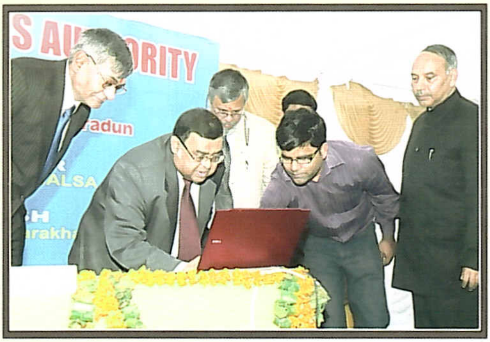

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA launching the Uttarakhand SLSA's website on 25th March, 2011 at Dehradun.

देहरादून, शनिवार 26 मार्च , 2011 सांध्य दैनिक प्रभात

मेगा लोक-अदालत में वेबसाइट का उद्घाटन करते न्यायाधीश अल्तमस कबीर व अन्य। छाया: प्रभात।

In order to reach the common masses via the electronic media, the website of the Uttarakhand State Legal Services Authority i.e. www.slsa.uk.gov.in was launched by Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge Supreme Court of India & Executive Chairman, National Legal Services Authority on 25th March, 2011 on the occasion of Mega Lok Adalat at Dehradun. This site contains the history of Uttarakhand SLSA, its activities with photographs, 34 valuable legal books namely "Saral Kannuni Gyan Mala" which can be easily downloaded, achievements of Uttarakhand SLSA and all information regarding accessibility to free legal services have been uploaded on the site. A common man can easily log-on to the aforesaid web-address and get the necessary information about beneficial schemes of the Uttarakhand State Legal Services Authority.

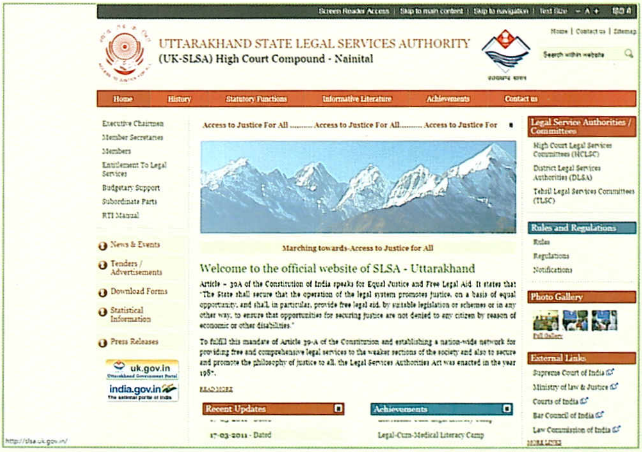

View of the Uttarakhand SLSA's website launched on 25th March, 2011 at Dehradun.

Newsletter of Uttarakhand State Legal Services Authority

For the purpose of imparting legal awareness, the inaugural issue of the Uttarakhand State Legal Services Authority's Newsletter was released by Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge Supreme Court of India & Executive Chairman, National Legal Services Authority on 25th March, 2011 on the occasion of Mega Lok Adalat at Dehradun, which contained the historical perspective of SLSA, an overview of the legal aid mechanism, achievements and its activities with statistical information.

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA, Hon'ble Mr. Justice Barin Ghosh, Chief Justice, High Court of Uttarakhand & Patron-In-Chief, UKSLSA with Hon'ble Mr. Justice Tarun Agarwala, Sr. Judge, High Court of Uttarakhand & Executive Chairman, UKSLSA launching the inaugural issue of the Uttarakhand SLSA's News Letter on 25th March, 2011 at Dehradun.

अमर उजाला

देहरादून | शनिवार | 26 मार्च 2011

न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने किया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट का उद्घाटन

संवेदनशील बनें न्यायिक अधिकारी

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने कहा कि विधिक सेवा में भाग लेने वाले न्यायाधीश और अधिवक्ता वादकारियों के प्रति संवेदनशील रवैया रखें। दून कोर्ट कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता से ही विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य सार्थक हो सकता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने कहा कि भारत के न्यायालयों में लाखों मुकदमे लंबित चल रहे हैं। इनके निपटारे के लिए सरकार एवं न्यायपालिका ने इस संबंध में कई प्रयास किए हैं। लोक अदालतें समस्या के निवारण में बहुत उपयोगी हैं।

न्यायमूर्ति ने चेताया भी कि लोक अदालतों के माध्यम से होने वाले समझौते हमेशा पाजीटिव हों जरूरी नहीं, समझौते निगेटिव भी हो सकते है। उन्होंने लीगल एड क्लीनिक और पैरा लीगल एडवाइजरी के संबंध में भी अपने विचार प्रकट किए और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड न्यायमूर्ति बारिन घोष ने कहा कि हाईकोर्ट में लंबित 37 हजार मामलों में से अब तक 20 हजार वादों का निस्तारण हुआ है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए न्यायपालिका दूर-दराज के इलाकों में पहुंच रही है।

न्यूज लेटर का विमोचन करते न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीजे बारिन घोष और विधिक प्राधिकरण सेवा के तरुण अग्रवाल।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने भी अपने विचार प्रकट किये। कार्यक्रम में समस्त न्यायिक अधिकारी, बार काउंसिल उत्तराखंड के सदस्य, दून बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्तागण और कई विधि छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान न्यूज लैटर का भी विमोचन किया गया।

Distribution of "Saral Kannuni Gyan Mala" Books to all the Gram Panchayat and Gram Sabha

Office/Fax 05942-236552
Office/(Direct) 05942-236762

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

Letter No. 40/SLSA/2011
Date 05.04.2011

प्रेषक, प्राथमिकता

सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

सेवा मे,

समस्त जिला जज/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

विषयः– जिले की समस्त ग्राम सभाओं में सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तका को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझ अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि जन–जन तक कानूनी सहायता कार्यक्रम एवं सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाओं के बहुमुखी प्रचार–प्रसार हेतु सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तको के दो–दो सैट (34 पुस्तकें) आपके जिलें में स्थापित समस्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से समस्त ग्राम सभाओ के ग्राम प्रधान को उपलब्ध करायी जानी है, ताकि वह समस्त व्यक्ति जोकि उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ इलाकों में निवास कर रहे है तथा सामान्य विधिक ज्ञान व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित व अज्ञान है, को इन पुस्तकों के माध्यम से कानूनी सहायता कार्यक्रम एवं सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाओ से भिज्ञ एवं लाभान्वित किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जनपद मे स्थापित समस्त ग्राम पंचायतो के माध्यम से समस्त ग्राम सभाओ के ग्राम प्रधान को सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकों के दो–दो सैट (34 पुस्तकें) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा तदउपरान्त समस्त पावती (सम्बन्धित ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान की मोहर व दिनांक सहित) की एक–एक छायाप्रति राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें, ताकि उक्त को मा0 कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मा0 मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

सादर।

भवदीय,
(प्रशान्त जोशी)
सदस्य–सचिव

Circular letter issued to all the DLSAs for providing the *"Saral Kannuni Gyan Mala"* books to each Gram Sabha of the State.

As per the valuable guidance given by Hon'ble the Patron-in-Chief and Hon'ble the Executive Chairman of the Uttarakhand SLSA in regard to creating vast legal awareness, particularly among those people, who reside in the far-flung areas of the hilly state of Uttarakhand and who are totally ignorant about this welfare schemes of the Govt., the Uttarakhand SLSA has taken concrete steps in this regard and accordingly directed all the District Legal Services Authorities to provide two sets of legal books namely "Saral Kannuni Gyan Mala" published by the Uttarakhand SLSA to each and every Gram Panchayat and Gram Sabha, so that the spirit of legal awareness may reach to the villagers at grass-root level.

A Legal Awareness Camp for the awareness of Panchayat Representatives

Hon'ble Mr. Justice Tarun Agarwala, Sr. Judge, High Court of Uttarakhand & Executive Chairman, Uttarakhand SLSA addressing the gathering in the legal awareness camp organized for the Panchayat representatives on 8th May, 2011 at Dehradun Law College.

Hon'ble Mr. Justice Tarun Agarwala, Sr. Judge, High Court of Uttarakhand & Executive Chairman, Uttarakhand SLSA presenting the "Saral Kannuni Gyan Mala" books to the Panchayat representatives on 8th May, 2011 at Dehradun Law College.

| दैनिक जागरण देहरादून, 9 मई 2011

प्रत्येक जनपद में बनेंगे न्याय भवन

शिविर

- लॉ कॉलेज के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर
- दोणपुर की पंचायत के जरिए फैलाई जागरूकता
- घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार आदि की दी जानकारी

लॉ कालेज की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में विचार रखती छात्रा व उपस्थित अतिथि।

देहरादून, जागरण संवाददाता: [illegible]

Hon'ble Mr. Justice Tarun Agarwala, Sr. Judge, High Court of Uttarakhand & Executive Chairman, Uttarakhand SLSA interacting with the Panchayat representatives on 8th May, 2011 at Dehradun Law College.

A legal awareness camp for the awareness of Panchayat representatives was organized on 8th May, 2011 in collaboration with the Dehradun Law College, at Dehradun wherein 21 Village Panchayats, which included Panchayat members, Chetrya Panchayat members, Zila Panchayat members, members of the self-help groups of the area and Law Students took part.

Hon'ble Mr. Justice Tarun Agarwala, Executive Chairman, Uttarakhand SLSA graced the aforesaid occasion and alongwith the budding Law Students, sensitized the Panchayat representatives about Panchayat Raj Institutions and their role in legal services mechanism. Legal literacy books like "Saral Kannuni Gyan Mala" published by the Uttarakhand SLSA were also distributed to the Panchayat Representatives.

Lok Adalat in High Court

हाईकोर्ट न्यूज

अमर उजाला

नैनीताल | रविवार | 22 मई 2011

हाईकोर्ट में लगी मेगा लोक अदालत

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित मेगा लोक अदालत में 36 वादों का निस्तारण कर 54 लाख 27 हजार प्रतिकर दिलाया गया। लोक अदालत में शनिवार को पारिवारिक एवं मोटर दुर्घटना के वादों का निस्तारण किया गया। इसमें 4 परिवारों का समझौता, 36 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें एमएसीटी के 26, क्रिमिनल के 7, पारिवारिक 3 वादों का निस्तारण हुआ।

एमएसीटी में पीड़ित परिवारों को 47 लाख 34 हजार रुपये का प्रतिकर तथा 6 लाख 93 हजार पारिवारिक वादों में दिलाया गया। लोक अदालत में वादों का निस्तारण मुख्य संरक्षक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष, कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की देखरेख में हुआ। इस मौके पर रजिस्ट्रार प्रशांत जोशी, जूडिशल नरेन्द्र दत्त, सहायक निबंधक मैनेजमेंट आफीसर नवीन चन्द्र किमारी, अधिवक्ता सीमा सिरोही, ललित शर्मा, संजय भट्ट, डीसीएस रावत आदि अधिवक्तागण मौजूद थे।

Under the valuable guidance of Hon'ble the Patron-In-Chief and Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, a Lok Adalat was held on 21[st] May, 2011 in the Hon'ble High Court by the High Court Legal Services Committee in collaboration with the Uttarakhand SLSA, wherein a total no. of 36 cases were amicably settled and a sum of Rs. 54,34,000/- was awarded as compensation.

Statistical Information

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LOK ADALATS HELD IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM JANUARY, 2011 TO JUNE, 2011

S. N.	Name of DLSA's	No. of Lok Adalats Held	No. of Cases Taken up	No. of Cases Disposed off	Compensation Awarded	Amount Realized As Fine (in Rs.)	No. of Persons Benefited in Lok Adalat
01	ALMORA	06	1,365	294	11,44,400.00	1,64,200.00	294
02	BAGESHWER	05	227	82	33,600.00	1,38,575.00	85
03	CHAMOLI	04	531	315	3,15,000.00	2,32,300.00	320
04	CHAMPAWAT	04	451	188	17,53,016.00	1,60,900.00	188
05	DEHRADUN	04	34,681	12,549	1,76,36,865.00	9,76,857.00	13,541
06	HARDWAR	03	6,391	3,868	61,86,544.00	17,17,650.00	3,946
07	NAINITAL	05	8,521	2,168	41,85,535.00	8,08,960.00	2,281
08	PAURI GARHWAL	03	2,622	734	36,22,500.00	2,41,440.00	786
09	PITHORAGARH	02	412	227	27,68,500.00	1,29,075.00	278
10	RUDRAPARYAG	05	623	380	25,18,016.00	1,18,771.00	439
11	TEHRI GARHWAL	10	1,624	400	7,42,000.00	2,89,375.00	460
12	U.S. NAGAR	04	7,540	2,948	41,30,720.00	11,80,975.00	3,167
13	UTTARKASHI	03	444	290	3,67,382.00	1,72,250.00	304
14	H.C.L. S. C. NTL	01	1,102	36	54,34,000.00	-	50
	TOTAL :-	59	66,534	24,479	5,08,38,078.00	63,31,328.00	26,139

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF CAMPS ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM JANUARY, 2011 TO JUNE, 2011

S. N.	Name of DLSA's	No. of Camps Organized	No. of Persons Benefited in Camps
01	ALMORA	07	1,710
02	BAGESHWER	06	1,200
03	CHAMOLI	01	90
04	CHAMPAWAT	02	525
05	DEHRADUN	03	750
06	HARDWAR	01	200
07	NAINITAL	01	325
08	PAURI GARHWAL	01	500
09	PITHORAGARH	03	1,050
10	RUDRAPARYAG	04	1,730
11	TEHRI GARHWAL	11	1,737
12	U.S. NAGAR	15	14,150
13	UTTARKASHI	03	900
14	H.C.L. S. C. NTL	-	-
15	U.K. S.L.S.A	-	-
	TOTAL :-	58	24,867

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LEGAL AID/ADVICE PROVIDED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM JANUARY, 2011 TO JUNE, 2011

S. N.	Name of DLSA's	No. of Persons Benefited through Legal Aid & Advice	
		Legal Aid	Legal Advice
01	ALMORA	03	-
02	BAGESHWER	-	-
03	CHAMOLI	06	-
04	CHAMPAWAT	04	-
05	DEHRADUN	15	-
06	HARDWAR	10	-
07	NAINITAL	-	-
08	PAURI GARHWAL	14	-
09	PITHORAGARH	06	-
10	RUDRAPARYAG	11	-
11	TEHRI GARHWAL	14	-
12	U.S. NAGAR	29	-
13	UTTARKASHI	05	-
14	H.C.L. S. C. NTL	-	-
15	U.K. S.L.S.A	34	-
	TOTAL :-	151	-

DISTRICT-WISE SCHEDULE FOR HOLDING MEGA LOK ADALAT FOR THE FINANCIAL YEAR 2011-12

District	Aug., 11		Sep., 11	Oct., 11	Nov., 11	Dec., 11	Jan., 12	Feb., 12	Mar., 12
Almora	2 Aug., 11	-	19 Sep., 11	-	24 Nov., 11	-	-	16 Feb., 12	-
Bageshwar	4 Aug., 11	-	21 Sep., 11	-	28 Nov., 11	-	-	18 Feb., 12	-
Chamoli	6 Aug., 11	-	23 Sep., 11	-	30 Nov., 11	-	-	20 Feb., 12	-
Champawat	-	1 Aug., 11	-	1 Oct., 11	-	1 Dec., 11	-	22 Feb., 12	-
Dehradun	-	3 Aug., 11	-	-	16 Nov., 11	-	10 Jan., 12	-	13 Mar., 12
Hardwar	-	5 Aug., 11	-	-	18 Nov., 11	-	12 Jan., 12	-	15 Mar., 12
Nainital	-	8 Aug., 11	-	3 Oct., 11	-	7 Dec., 11	-	24 Feb., 12	-
Pauri Garhwal	-	10 Aug., 11	-	12 Oct., 11	-	9 Dec., 11	-	27 Feb., 12	-
Pithoragarh	-	12 Aug., 11	-	14 Oct., 11	-	12 Dec., 11	-	-	1 Mar., 12
Tehri Garhwal	-	18 Aug., 11	-	17 Oct., 11	-	14 Dec., 11	-	-	3 Mar., 12
Rudraprayag	-	20 Aug., 11	-	19 Oct., 11	-	16 Dec., 11	-	-	5 Mar., 12
Uttarakashi	-	24 Aug., 11	-	21 Oct., 11	-	19 Dec., 11	-	-	7 Mar., 12
U.S. Nagar	-	29 Aug., 11	-	31 Oct., 11	-	24 Dec., 11	-	-	9 Mar., 12

NOTE:
- Monthly Lok Adalats shall also be held in each district, preferably on last Saturday of every month.
- At least Four Legal Literacy Camps shall also be organized in a year in each district, preferably on first Sundays of the month.

SCHEDULE FOR HOLDING MEGA LOK ADALATS IN HIGH COURT FOR THE FINANCIAL YEAR 2011-12

August, 2011	December, 2011	March, 2012
27 August, 2011 (Saturday)	22 December, 2011 (Thursday)	16 March, 2012 (Friday)

DISTRICT-WISE SCHEDULE FOR ORGANIZING SEMINAR FOR THE FINANCIAL YEAR 2011-12

District	September, 2011	February, 2012
Almora	24 Sep., 11	22 Feb., 12
Bageshwar	28 Sep., 11	27 Feb., 12
Chamoli	14 Sep., 11	13 Feb., 12
Champawat	30 Sep., 11	29 Feb., 12
Dehradun	5 Sep., 11	3 Feb., 12
Hardwar	3 Sep., 11	1 Feb., 12
Nainital	22 Sep., 11	20 Feb., 12
Pauri Garhwal	9 Sep., 11	8 Feb., 12
Pithoragarh	26 Sep., 11	24 Feb., 12
Tehri Garhwal	7 Sep., 11	6 Feb., 12
Rudraprayag	12 Sep., 11	10 Feb., 12
Uttarakashi	16 Sep., 11	15 Feb., 12
U.S. Nagar	20 Sep., 11	17 Feb., 12

NOTE:
- Monthly Lok Adalats shall also be held in each district, preferably on last Saturday of every month.
- At least Four Legal Literacy Camps shall also be organized in a year in each district, preferably on first Sundays of the month.

SCHEDULE FOR ORGANIZING SEMINAR IN HIGH COURT FOR THE FINANCIAL YEAR 2011-12

October, 2011	Feb, 2012
21 October, 2011 (Friday)	21 February, 2011 (Tuesday)

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

CONTACT US

S. NO.	DESIGNATION	ADDRESS	CONTACT NUMBERS
01	Member Secretary	Uttarakhand State Legal Services Authority High Court Compound, Nainital	Office: 05942-236762, 236552 Fax: 05942-236552
02	Secretary	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Office:05942-232085 Fax: 05942-237721
03	Chairman	District Legal Services Authority, Almora	Office: 05962-231105
04	Chairman	District Legal Services Authority, Bageshwar	Office: 05963-221844
05	Chairman	District Legal Services Authority, Chamoli,	Office: 01372-251529
06	Chairman	District Legal Services Authority, Champawat	Office: 05965-211202
07	Chairman	District Legal Services Authority, Hardwar	Office: 01334-239780
08	Chairman	District Legal Services Authority, Dehradun	Office: 0135-520873
09	Chairman	District Legal Services Authority, Nainital	Office: 05942-237159
10	Chairman	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Office: 01368-221815
11	Chairman	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Office: 05964-228322
12	Chairman	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Office: 01364-233796
13	Chairman	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Office: 01376-233424
14	Chairman	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Office: 05944-250682
15	Chairman	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Office: 01374-226557